

वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण 2015-16

अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन

हाल के वर्षों में कई तब्दीलियों और चुनौतियों से सफलतापूर्वक जूझते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था सशक्त नीतियों और नूतन आशावाद के मौजूदा चक्रीय दोहराव के दौर में आ पहुंची है। अर्थव्यवस्था ने पिछले दिनों निम्न विकास, उच्चस्तरीय मुद्रास्फीति और चालू खाता घाटा बढ़ने और असहयोगकारी की बाह्य वातावरण सरीखे इम्तहानों का सामना किया है। मन्द स्फीति तथा प्रबन्धनीय मौजूदा लेखा सन्तुलनों, स्थिर रूप और बढ़ता हुआ विदेशी मुद्रा भन्डार, जिसके संकेत बृहद-आर्थिक स्थिरता में दिखते हैं, के साथ ही विकास बहाल हुआ है। केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार बाजार मूल्यों (2011-12) पर स्थिर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के रूप में मापित अर्थव्यवस्था की विकास दर 2012-13 में 5.1 प्रतिशत थी जोकि 2013-14 में 6.9 प्रतिशत हो गई और 2014-15 में जिसके 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान था। भारत दुनिया के उन चुनीदा देशों में से एक है जिनके लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने अपने विकास अनुमानों में वृद्धि की है। अर्थव्यवस्था की पुनर्बहाली इस तथ्य के आलोक में उल्लेखनीय है कि यह अस्थिर वैश्विक आर्थिक स्थितियों और अपेक्षा से कमतर घरेलू कृषि मौसम के बावजूद ऐसा हुआ है।

वर्ष 2014-15 कई महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों का साक्षी रहा है जिनमें बहाली के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की अवसंरचनागत बाधाओं से पार पाने का लक्ष्य रखा गया था। इस दिशा में की गई नीतिगत कार्रवाई में मुद्रास्फीति और विदेशी क्षेत्र के प्रति सन्तुलनों को नियंत्रित करने के लिए अल्प आवधिक और अन्तरणों तथा विकास के लिए एक मध्यम व दीर्घ आवधिक आर्थिक प्रबन्धों, प्रमुख सुधारों में यथाघोषित उपायों जिनका लक्ष्य पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस क्षेत्र में प्रशासित मूल्य का युक्तिसंगत नियंत्रण, अवसंरचना विकास तथा अर्थव्यवस्था की अड़चनों, विकास (उसमें निहित पुनर्वास जरूरतों के साथ-साथ) के लिए भूमि अधिग्रहण की राह को बाधामुक्त करना और कोयला तथा विद्युत जैसे महत्वपूर्ण अवदानों की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित बनाए रखना, आदि शामिल था। सरकार का विकास एजेन्डा विनिर्माण की बहाली से थम गया था जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के उदारीकरण के साथ-साथ निवेश सुविधाओं तथा उपायों की भारी मात्रा के साथ-साथ बचत में सुधार आदि उपायों के कारण "मेक इन इंडिया" में चल पड़ा है।

बजट 2014-15 में अपने विकास एजेंडे के साथ-साथ सरकार के आर्थिक उपायों, यथोचित नीतियों तथा विधायी पहलों को

व्यापक रूप से प्रतिपादित किया गया था। प्रधान मंत्री जन धन योजना एक युगान्तरकारी पहल है जिसमें अभी तक आर्थिक सेवाओं के दायरे से बाहर रह रहे वंचित लोगों के लिए जमा और बीमा की सुविधा के साथ बैंक खाते खोले गए हैं। आधार से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ अन्तरणों से सब्सिडी सुपुर्दगी में उच्च स्तरीय दक्षता बढ़ेगी। बहु प्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत किया गया है और इस दिशा में केंद्र तथा राज्यों के बीच विश्वास बहाली के लिए काम चल रहा है और मौजूदा वर्ष में केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) प्रतिपूर्ति के पहले हिस्से की घोषणा कर दी गई है।

व्यय सुधार आयोग व्यय सुधारों की जरूरतों को भी देख रहा है और शीघ्र ही वह आवंटन-दक्षता में सुधार के सम्बन्ध में कतिपय सुझाव देगा। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के लिए भी एक कारगर कार्यक्रम तैयार किया है। सरकार को उम्मीद है कि वह 2014-15 में स.घ.उ. (जी.डी.पी.) अनुपात के लक्षित राजकोषीय घाटा स्तर को प्राप्त कर लेगी।

हाल के महीनों में थोक तथा उपभोक्ता मूल्यों में स्फीति में भरोसेमंद गिरावट आई है। कच्चे तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में हो रही लगातार गिरावट, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) की चुस्त मौद्रिक नीतिगत पहलों और राजकोषीय विवेक की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता ने मिलजुल कर देश में मुद्रास्फीति को घटाए रखने में मदद की है।

मूल्य स्थिरता का मौजूदा परिदृश्य और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सहमत प्रत्याशाएं मुद्रास्फीति घटाने में सहायक होंगी और प्रकारान्तर से ये शनैः शनैः विकास को बढ़ाने वाली ही होंगी। अपनी एक के बाद एक दो घोषणाओं में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर के 25 आधार बिंदु घटाने (7.75 प्रतिशत तक) तथा एस.एल.आर. के 50 आधार बिंदु घटाने (21.5 प्रतिशत तक) की घोषणा की है।

इस वर्ष विदेशी मुद्रा बाजार में कम अस्थिरता भी रही क्योंकि 2013-14 की तुलना में 2014-15 के दौरान रुपया तुलनात्मक रूप से स्थिर रहा। रुपया अगस्त, 2013 के ₹68 प्रति डालर के स्तर से नीचे आकर 2014 (जनवरी-दिसंबर) में लगभग ₹60.97 प्रति डालर के औसत पर स्थिर रहा। 2014-15 की पहली छमाही में चालू खाता घाटा स.घ.उ. के 1.9 प्रतिशत पर बना रहा। निवल पूंजी अंतर्वाह अप्रैल-सितंबर 2014-15 में बढ़कर 36.0 बिलियन अमरीकी डालर हो गया, जबकि 2013-14 की इसी अवधि में यह 16.3 बिलियन अमरीकी डालर था।

स.घ.उ. विकास दर

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए गए अग्रिम अनुमानों के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था में, 2012-13 और 2013-14 में क्रमशः 5.1 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत की विकास दर की तुलना में, 2014-15 में 7.4 प्रतिशत की विकास दर अनुमानित है। 2014-15 में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में विकास दर में काफी सुधार हुआ जबकि कृषि क्षेत्र में विकास दर, कम मानसून के चलते गिर गई। 2014-15 में रिकार्ड उच्चतर विकास दर दर्ज होने के अनुमान विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं, वित्तीय, स्थावर भू-संपदा और पेशेवर सेवाओं, लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं क्षेत्र में है।

2014-15 के (अप्रैल-दिसंबर 2014) पहली तीन तिमाहियों में स.घ.उ. की विकास दर, 2013-14 की पहली तीन तिमाहियों में 7.1 प्रतिशत के मुकाबले 7.4 प्रतिशत बैठती है। तिमाही-वार, 2014-15 की पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही के लिए अनुमान क्रमशः 7.0 प्रतिशत, 7.8 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत हैं।

मांग पक्ष से, स्थिर मूल्यों पर अंतिम उपभोग व्यय में वृद्धि 2012-13 में 4.9 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 6.5 प्रतिशत और अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2014-15 में यह और बढ़कर 7.6 प्रतिशत तक होने का अनुमान है। सकल नियत पूंजी निर्माण में वृद्धि भी 2012-13 में -(0.3) प्रतिशत से सुधारकर 2013-14 में 3.0 प्रतिशत हो गई और 2014-15 में इसमें और सुधार होकर 4.1 प्रतिशत होने की आशा है। 2014-15 में वास्तविक रूप से आयातों में 0.5 प्रतिशत तक की गिरावट अनुमानित है जबकि वास्तविक निर्यातों में 0.9 प्रतिशत तक की वृद्धि परियोजित है।

कृषि

2014 की दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु के दौरान, देश में दीर्घावधि औसत (एलपीए) की तुलना में 12 प्रतिशत कम वर्षा हुई। 4वें अग्रिम अनुमानों के अनुसार, खाद्य अनाजों का उत्पादन 2012-13 (अंतिम अनुमानों) में 257.13 मिलियन टन की तुलना में 2013-14 के दौरान 264.77 मिलियन टन (चावल 106.54 मिलियन टन और गेहूं 95.91 मिलियन टन) रहा है दालों का उत्पादन 19.27 मिलियन टन, गन्ने का 350.02 मिलियन टन तिलहन का 32.87 मिलियन टन और कपास का 170 कि. ग्रा. प्रत्येक की 36.59 मिलियन गांठें रहने का अनुमान है। 19.9.2014 को कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, कुल खरीब खाद्य अनाजों का उत्पादन 2012-13 में 117.18 मिलियन टन और 2013-14 में 129.32 मिलियन टन की तुलना में 2014-15 के दौरान 120.27 मिलियन टन रहने का अनुमान है।

2013-14 में कृषि ऋण का प्रवाह 2003-04 में ₹86,981 करोड़ और 2012-13 में ₹6,07,375 करोड़ की तुलना में बढ़कर

₹7,11,621 करोड़ हो गया। 2014-15 के लिए कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य ₹8,00,000 करोड़ नियत किया गया था।

कीमते

खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति कम होने के कारण हेडलाइन थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति 2013-14 में 6 प्रतिशत से कम होकर 2014-15 (अप्रैल-दिसंबर) में 3.4 प्रतिशत रह गई। डब्ल्यूपीआई खाद्य मुद्रास्फीति (प्राथमिक खाद्य वस्तुओं और विनिर्मित खाद्य उत्पादों को मिलाकर) जो 2013-14 के दौरान 9.4 प्रतिशत के स्तर पर उच्च बनी हुई थी, दिसंबर, 2013 से सखिजियों के मूल्यों में तीव्र सुधारों (मार्च, 2014 को छोड़कर) और अनाजों तथा अण्डा, मांस एवं मछली के मूल्यों में नरमी के चलते 2014-15 (अप्रैल-दिसंबर) में कम होकर 4.8 प्रतिशत हो गई। तथापि, मुख्य (खाद्य-भिन्न विनिर्मित उत्पाद) मुद्रास्फीति 2013-14 के दौरान 2.9 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 (अप्रैल-दिसंबर) में बढ़कर 3.2 प्रतिशत हो गई।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - नई श्रृंखला (आधार वर्ष 2010 के साथ) के अनुसार हेडलाइन सीपीआई 2013-14 में 9.5 प्रतिशत के मुकाबले 2014-15 (अप्रैल-दिसंबर) में औसतन 6.8 प्रतिशत रही। सीएसओ ने आधार वर्ष को संशोधित करके 2010 से 2012 करके संशोधित श्रृंखला 12 फरवरी, 2015 को जारी की है। संशोधित श्रृंखला के अनुसार, सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति जनवरी, 2015 में 5.1 प्रतिशत रही।

उद्योग और सेवाएं

औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक पर आधारित प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों का निष्पादन जो 2011-12 से मंद पड़ गया था उसके 2014-15 में औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्तियों में उलटाव दर्शाया है। विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि की गति बढ़ाने में रुकावट वाले कारकों में उच्च ब्याज दर, अवसंरचना संबंधी अड़चने और निम्न घरेलू व बाह्य मांग शामिल हैं। प्रयोग - आधारित वर्गीकरण के अर्थ में, बुनियादी वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं में अप्रैल-दिसंबर 2014-15 के दौरान वृद्धि में काफी सुधार देखा गया है। जबकि मध्यवर्ति वस्तुओं में वृद्धि मंद बनी रही। अप्रैल-दिसंबर 2014-15 में खासकर उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु क्षेत्र में संकुचन के कारण उपभोक्ता वस्तुएं संकुचित हो गईं।

सेवा क्षेत्र में वृद्धि 2012-13 में 8.0 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 9.1 प्रतिशत हो गई। सीएसओ के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, सेवाओं में वृद्धि 2014-15 और बढ़कर 10.6 प्रतिशत हो गई। 2014-15 में क्षेत्रवार व्यापार, होटल, परिवहन और संचार सेवाएं 8.4 प्रतिशत, वित्तीय, स्थावर संपदा और व्यवसायिक सेवाएं 13.7 प्रतिशत और लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाएं 9.0 प्रतिशत बढ़नी अनुमानित है।

वैदेशिक क्षेत्र

गड़बड़ी के आरंभिक चरण के बाद 2013-14 में वैदेशिक क्षेत्र

का समग्र परिणाम निम्न व्यापार और चालू खाता घाटे के चलते संतुलित था और प्रचूर वित्तीय प्रवाहों के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा भंडार में संग्रहण हुए। यह प्रक्रिया चालू वित्त वर्ष में भी जारी रहेगी।

भारत का पण्य व्यापार (सीमा शुल्क आधार पर) वर्षानुवर्ष 4.7 प्रतिशत बढ़कर 2013-14 में 314.4 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गया। अप्रैल-जनवरी 2014-15 के दौरान भारत के निर्यात 2.4 प्रतिशत बढ़े और ये 265.0 बिलियन डालर मूल्य के थे। भारत के आयात वर्षानुवर्ष 8.3 प्रतिशत गिरकर 2013-14 में 450.2 बिलियन अमरीकी डालर पर आ गए। 2014-15 (अप्रैल-जनवरी) में भारत का आयात 383.4 बिलियन अमरीकी डालर था जो 2013-14 (अप्रैल-जनवरी) की तुलना में 2.2 प्रतिशत की वृद्धि का संकेत देता है। यह जुलाई 2014 के बाद से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मंदी से उत्पन्न पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक के आयात में 7.9 प्रतिशत की मंदी और पीओएल-भिन्न आयातों में 7.8 प्रतिशत (258.7 बिलियन अमरीकी डालर) वृद्धि से हुआ था। सोने और चांदी के पीओएल-भिन्न आयात अप्रैल-जनवरी, 2014-15 में (वर्षानुवर्ष) 8.0 प्रतिशत बढ़े थे। उपर्युक्त घटनाक्रम के परिणामस्वरूप अप्रैल-जनवरी 2014-15 में व्यापार घाटा 118.4 बिलियन अमरीकी डालर हुआ था।

चालू वित्त वर्ष 2014-15 का भुगतान शेष संबंधी डाटा पहले छह महीने का ही उपलब्ध है। भुगतान शेष संबंधी व्यापार घाटा अप्रैल-सितंबर 2013 में 83.8 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में अप्रैल-सितंबर 2014 में 73.2 बिलियन अमरीकी डालर था। 2014-15 के पूर्वार्ध में 55.3 बिलियन अमरीकी डालर (2013-14 के पूर्वार्ध में 56.8 बिलियन अमरीकी डालर) की निवल अदृश्य प्राप्तियों के आधिक्य के चलते चालू खाता घाटा अप्रैल-सितंबर, 2013 में 26.9 बिलियन अमरीकी डालर में अप्रैल-सितंबर 2014 में 17.9 बिलियन अमरीकी डालर था।

वर्ष 2013-14 (अप्रैल-सितंबर) में वित्तीय (पूंजी) प्रवाह चालू खाता घाटे के स्तर से कम थे जिससे प्रारक्षित भंडार में आहरण द्वारा कमी हुई। तथापि, 2014-15 (अप्रैल-सितंबर) के पूर्वार्ध में 36.0 बिलियन अमरीकी डालर पर वित्तीय प्रवाह चालू खाता घाटे से बढ़ गए और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 18.1 बिलियन अमरीकी डालर के संग्रहण हुए थे। इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा भंडार के स्टाक में वृद्धि हुई जो सितंबर-अंत 2014 में 313.8 बिलियन अमरीकी डालर थी। विदेशी मुद्रा भंडार का स्टाक संबंधी उपलब्ध डाटा 6 फरवरी 2015 को 330.2 बिलियन अमरीकी डालर था। चूंकि कुछ वित्तीय प्रवाह ऋण सृजित करने वाले थे फिर भी विदेशी ऋण का कुल स्टाक मार्चान्त 2014 में 442.3 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर की तुलना में सितंबर-अंत 2014 में 455.9 बिलियन अमरीकी डालर था।

चालू खाता घाटे के स्तरों की तुलना में वित्तीय प्रवाहों की प्रचूरता और प्रारक्षित मुद्रा संग्रहण के स्तरों का रूप की विनिमय

दर में घटबढ़ पर प्रभाव था। चालू वित्त वर्ष में ₹59.31 से ₹62.75 के बीच प्रति अमरीकी डालर की मासिक औसत विनिमय दर तुलनात्मक रूप से स्थिरता इंगित कर रही है। माह-दर-माह आधार पर रुपया में मूल्यह्रास 2.8 प्रतिशत हुआ जो मार्च 2014 में ₹61.01 प्रति अमरीकी डालर से दिसंबर 2014 में ₹62.75 प्रति अमरीकी डालर हो गया। इसमें किंचित् मूल्यवर्धन से यह जनवरी 2015 में ₹62.23 प्रति अमरीकी डालर था।

मुद्रा, बैंकिंग और पूंजी बाजार

वर्ष 2014-15 के दौरान नकदी की स्थिति मोटे तौर पर संतुलित बनी रही। जुलाई-अगस्त 2014 के दौरान मांग बाजार में उच्च अस्थिरता को देखते हुए और नकदी प्रबंधन संचालनों में लोचशीलता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी नकदी प्रबंधन कार्ययोजना संशोधित कर दी जो 5 सितंबर 2014 से प्रभावी हो गई है। संशोधित नकदी प्रबंधन कार्ययोजना के क्रियान्वयन ने ओवरनाइट अंतर बैंक घटक में अस्थिरता घटाने और मांग दर को बेहतर रूप से नीतिगत रेपो दर के पास लाकर स्थिरता देते हुए सहायता की है। संशोधित नकदी प्रबंधन कार्ययोजना ने 14-दिवसीय आवधिक रेपो नीलामियों में भारत औसत कट-आप दरों के साथ-साथ ओवरनाइट परिवर्तनशील दर रेपो नीलामियों को रेपो दर के आसपास बने रहने में सहायता की। भारत औसत मांग दर की अस्थिरता में कमी आई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत संचार के लिए सांकेतिक स्थिर (शीर्ष उ.मू.सू.) के उपाय के रूप में नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अंगीकार किया है। इस वित्त वर्ष के दौरान जनवरी, 2015 तक भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरें अपरिवर्तित रखीं। मुद्रास्फीति के दबावों की सुकरता को जारी रखने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 जनवरी, 2015 को नकदी समायोजन सुविधा के तहत नीतिगत रेपो दर 8.0 प्रतिशत से घटाकर 7.75 प्रतिशत कर दी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 फरवरी, 2015 को घोषित अद्यतन द्विमासिक नीतिगत विवरण में, नकदी समायोजन सुविधा (एसएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर 7.75 पर अपरिवर्तित रखी गई हैं, अनुसूचित बैंकों का नकदी आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर), निवल मांग और मियादी देनदारियां 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहीं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 फरवरी, 2015 से आरम्भ होने वाले पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सांविधिक नकदी अनुपात (एसएलआर) 50 आधार बिन्दु तक घटकर उनकी एनडीटीएल का 22.0 प्रतिशत से 21.5 प्रतिशत रह गया; और इससे निर्यात ऋण पुनर्वित्त का स्थान प्रणाली स्तर की नकदी के प्रावधान ने ले लिया।

वित्तीय समावेशन

देश की वृहत असेवित जनसंख्या को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके और इसके विकास की संभावना को मुक्त करने के लिए वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 28 अगस्त, 2014 को प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) आरम्भ की

गई थी। इस योजना में प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाते, वित्तीय साक्षरता, ऋण और बीमा तक पहुँच के साथ बैंकिंग सुविधा तक सार्वभौमिक पहुँच की परिकल्पना की गई है। इसके तहत लाभार्थियों को ₹1 लाख के दुर्घटना बीमा कवर की अंतर्निहित सुविधायुक्त रूपे डेबिट कार्ड प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, 15 अगस्त, 2014 और 26 जनवरी, 2015 के बीच प्रथम बार अपना खाता खोलने वाले और योजना की अन्य अर्हता शर्तें पूरी करने वाले व्यक्तियों को ₹30,000 का जीवन बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा। 28 जनवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार, 12.31 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से 7.36 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और 4.95 करोड़ शहरी क्षेत्रों में हैं।

पूंजी बाजार

अप्रैल-दिसम्बर, 2014 के दौरान, प्राथमिक बाजार के संसाधन जुटाने में वर्षानुवर्ष आधार पर इक्विटी और ऋण मुद्दों में गिरावट और निजी संस्थापनों में बढ़ोतरी की मिश्रित प्रतिक्रिया देखने में आई। चूंकि निजी संस्थापनों का हिस्सा काफी अधिक बैठता है, इसलिए इस अवधि के दौरान कुल संचित राशि में बढ़ोतरी हुई। इस अवधि के दौरान, एनएसई और बीएसई दोनों के ही निजी संस्थापनों की संख्या और मूल्य में वृद्धि हुई।

न्यूनतम मानदंड सूचकांकों, बीएसई, सेंसेक्स और निफ्टी में चालू वर्ष में अब तक वर्षानुवर्ष आधार पर 29.9 प्रतिशत और 31.4 प्रतिशत की तदनुरूप वृद्धि दरों के साथ 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार, क्रमशः 27499.4 और 8282.7 पर बन्द होने के चलते एक सामान्य उर्ध्वगामी प्रवृत्ति दिखाई दी। भारतीय सूचकांक, विश्व में बेहतर निष्पादक सूचकांकों में आते हैं।

1 जून, 2014 से, पूर्ववर्ती विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) के स्थान पर एफपीआई प्रणाली को आरम्भ करने से, उप-लेखाओं और अर्हक विदेशी निवेशकों (क्यूएफआई) को एक नई निवेशक श्रेणी में आमेहित कर दिया गया है जिसे

"विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) कहा जाता है।" अप्रैल-दिसम्बर, 2014 के दौरान कुल निवल एफपीआई अंतर्वाह 2013-14 की तदनुरूप अवधि में 539 बिलियन अमरीकी डालर बहिर्वाह की तुलना में 32,943 बिलियन अमरीकी डालर पर स्थिर रहा।

संभावनाएं

2014-15 के पहले नौ महीनों में सब्सिडी के क्षेत्र में कुछ प्रमुख नीतिगत सुधार देखे गए; आशोधित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्कीम शुरू की गई, नई गैस मूल्य निर्धारण नीति का अनुमोदन किया गया है और डीजल की कीमतें नियंत्रणमुक्त की गई हैं। राजकोषीय सुदृढीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यय सुधार की विभिन्न पहलुओं की जांच करने हेतु व्यय प्रबंधन आयोग का गठन किया गया है। यह अधिकतम परिणाम हासिल करने के लिए सरकारी व्यय के आबंटनात्मक और कार्यशील क्षमताओं की समीक्षा करेगा।

सुधार के प्रति सरकार की वचनबद्धता से प्रकट होने वाले सकारात्मक संकेतों, तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के कारण अनुकूल परिस्थिति और सुखद स्फीतिकारी संभावना जिससे भारतीय रिजर्व बैंक के लिए मौद्रिक नीति को सुखद बनाने की गुंजाइश होगी, को देखते हुए 2015-16 में विकास की संभावनाएं उज्ज्वल प्रतीत होती हैं। जबकि औद्योगिक क्षेत्र धीरे-धीरे गति पकड़ रहा है, सेवा क्षेत्र के सभी प्रमुख खण्डों में विकास की गति तेज है। घरेलू खपत में विकास में तेजी आयी है, सरकार द्वारा किए गए सुधार और सुविधा प्रदान करने के उपायों के कारण निवेश के मजबूत होने की संभावना है, विदेशी पूंजी अंतर्वाह में उछाल आया है और अर्थव्यवस्था में कारोबार की आशावादिता बढ़ी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था से उत्पन्न प्रमुख अधोमुखी जोखिम यह है कि अभी तक स्थायी विकास की वापसी नहीं हुई है। उपर्युक्त के आलोक में, निम्न मुद्रास्फीति बाह्य क्षेत्र में स्थिरता और सामान्य मानसून के मद्देनजर अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2015-16 के दौरान लगभग 8.5 प्रतिशत रहने की संभावना है।

वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण
(आर्थिक कार्य निष्पादन : एक दृष्टि में)

क्र.सं.	मद	निरपेक्ष मूल्य अप्रैल-दिसम्बर		प्रतिशत परिवर्तन अप्रैल-दिसम्बर	
		2013-14	2014-15	2013-14	2014-15
संपदा क्षेत्र					
1.	उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (₹ हजार करोड़) @				
	(क) वर्तमान मूल्यों पर	11345	12654	13.6	11.5
	(ख) 2011-2012 के मूल्यों पर	9921	10657	6.9	7.4
2.	औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (2004-05=100)	168.3	171.8	0.1	2.1
3.	थोक मूल्य सूचकांक (2004-05=100)	177.0	182.9	6.2	3.4
4.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक: नई श्रृंखलाएं (2010=100)	134.2	143.3	9.9	6.8
5.	मुद्रा आपूर्ति (एम3) (₹ हजार करोड़)	9223	10250	14.8	11.1
6.	वर्तमान मूल्यों पर आयात**				
	(क) ₹ करोड़	2028361	2134283	2.2	5.2
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर	338907	351206	-7.0	3.6
7.	वर्तमान मूल्यों पर निर्यात**				
	(क) ₹ करोड़	1395187	1465171	17.8	5.0
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर	231830	241154	6.6	4.0
8.	व्यापार घाटा (मिलियन अमरीकी डालर)**	-107077	-110052	-27.1	2.8
9.	विदेशी मुद्रा भंडार (जनवरी अंत तक)				
	(क) ₹ करोड़	1818514	2031369	15.5	11.7
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर	291070	328689	-1.5	12.9
10.	चालू खाता शेष (मिलियन अमरीकी डालर)##	-26959	-17942		
सरकारी वित्त साधन #					
1.	राजस्व प्राप्तियां	633933	693773	11.1	9.4
2.	कर राजस्व (निवल)	517661	545714	6.9	5.4
3.	कर-भिन्न राजस्व	116272	148059	34.6	27.3
4.	पूँजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	529858	542615	26.0	2.4
5.	ऋणों की वसूली	8038	8282	4.3	3.0
6.	अन्य प्राप्तियां	5430	1952	-33.6	-64.1
7.	उधार और अन्य देनदारियां	516390	532381	27.6	3.1
8.	कुल प्राप्तियां (1+4)	1163791	1236388	17.4	6.2
9.	आयोजना-भिन्न व्यय	812528	883757	16.9	8.8
10.	राजस्व खाता	731159	813270	16.9	11.2
<i>जिसमें:</i>					
11.	ब्याज भुगतान	248464	275220	23.0	10.8
12.	पूँजी खाता	81369	70487	16.9	-13.4
13.	आयोजना व्यय	351263	352631	18.7	0.4
<i>जिसमें:</i>					
14.	राजस्व खाता	274016	282278	12.8	3.0
15.	पूँजी खाता	77247	70353	46.0	-8.9
16.	कुल व्यय (9+13)	1163791	1236388	17.4	6.2
17.	राजस्व व्यय (10+14)	1005175	1095548	15.7	9.0
18.	पूँजी व्यय (12+15)	158616	140840	29.4	-11.2
19.	राजस्व घाटा (17-1)	371242	401775	24.6	8.2
20.	राजकोषीय घाटा {16-(1+5+6)}	516390	532381	27.6	3.1
21.	प्राथमिक घाटा (20-11)	267926	257161	32.2	-4.0

** सीमाशुल्क आधार पर। # महालेखा नियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा संसूचित आंकड़े।

@ स.घ.उ. अप्रैल से मार्च तक। 2014-15 के अनुमान अग्रिम अनुमान हैं। ## अप्रैल - सितंबर